5 विलक्षण प्रतिभा के धनी अमित शाह

7 तेजस बाथम ने जीती स्कूल चैंपियनशिप

8 कृषि उपज मंडी की अव्यवस्थाओं से किसान

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 51 | प्रति सोमवार, 28 अप्रैल 2025 | मूल्य : दो रुपये | पृष्ठ : 8

बिजनेसमैन दिलीप सूर्यवंशी ने भाजपा को दिया 29 करोड़ का चंदा

▪ क्या चंदे कारण दिलीप बिल्डकॉन में पार्टनर देवेंद्र जैन एवं अन्य अधिकारियों को मिला सीबीआई से अभयदान?

कवर स्टोरी
-विजया पाठक
एडिटर

सत्ता का प्रसाद और भागीदारी से कैसे कोई फर्श से अर्श पर पहुंचता है इसका उदाहरण बिजनेसमैन दिलीप सूर्यवंशी। 2003 में बीजेपी की सरकार बनते ही दिलीप सूर्यवंशी के भाग्य बदल गए। कभी छोटे-मोटे ठेके उठाने वाला व्यक्ति कैसे भाजपा सरकार के 18 साल में बिजनस टाईकुन बन गया। इनका उस समय वो रसूख था कि कहा जाता है कि कलेक्टर/एसपी की सूची इनके ऑफिस से फाइनल होती थी। सरकार अगर मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में इनके पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट की जांच की गई तो देश का एक बड़ा घोटाला उजागर होगा। यहां तक इनके अनैतिक काम करने के डर से एक ईएनसी ने नौकरी से इस्तीफा देना ही बेहतर समझा था। क्या प्रदेश, क्या देश बड़े-बड़े ठेके दिलीप बिल्डकॉन को मिलने लगे थे। पर कहते हैं हर दिन एक जैसा नहीं होता। सत्ता से बेरुखी के कारण 2019 से इनको व्यापार में घाटा होना चालू हुआ, इनके कुछ प्रोजेक्ट फ़ेल हुए। साथ-साथ इनके कुछ धंधों में अडानी समूह ने दिलचस्पी दिखाना चालू किया था। इसी कड़ी में सीबीआई ने दिलीप बिल्डकॉन के कार्यकारी निदेशक देवेंद्र जैन, जीएम रत्नाकरण साजीलाल, सुनील कुमार, अनुज गुप्ता को हिरासत में लिया। अब जब चारों तरफ से परेशानियों में घिरे दिलीप बिल्डकॉन ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 29 करोड़ का चंदा देकर करीब-करीब अपनी सारी परेशानियों से निजात पा ली है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की ओर से जारी रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले दो दशकों में फर्श से अर्श पर पहुंचे भोपाल के मशहूर बिजनेसमेन दिलीप सूर्यवंशी अब देश के टॉप 10 दानदाताओं में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप सूर्यवंशी ने भाजपा को पिछले साल में 29 करोड़ रुपए स्किम डोनेशन दिया है। (शेष पेज 2 पर)

क्या दिलीप सूर्यवंशी के 200 करोड़ से खरीदे विधायकों से गिरी थी कमलनाथ सरकार?

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सेना पर उठाया सवाल

-विजया पाठक

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में एक तरफ जहां पूरे देश में गुस्से का माहौल है वहीं दूसरी तरफ देश के नेता इस पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचारी नेता भूपेश बघेल ने दो दिन पहले इस पूरी घटना पर जो बयानबाजी की है वह पूरी तरह निंदनीय है। देश के निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले पर बघेल ने बनियाबाजी करते हुए देश की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार पर प्रश्न उठाया है। (शेष पेज 2 पर)

राष्ट्र से पहले राज्यों में मजबूत करनी होगी कांग्रेस, हिंदी भाषी राज्यों पर करना होगा फोकस

▪ संगठन को भी मतबूत करने की जरूरत

▪ कमलनाथ, अरूण यादव, सचिन पायलट, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत जैसे कर्मठ नेताओं को सौंपी जाये राज्यों की कमान

-विजया पाठक

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का एक समय था जब वह संपूर्ण देश में पार्टी का राज हुआ करता था। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस धीरे-धीरे एक सीमित क्षेत्र में सिमटती नजर आ रही है। खासकर दक्षिण के अलावा अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस का वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है। जबकि देश के हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस का पतन लगातार जारी है। कांग्रेस आलाकमान को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि यह भी सच है कि अभी भी कांग्रेस देश की नंबर दो पार्टी है। (शेष पेज 3 पर)

बेटी हर्षिता की शादी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उड़ाये 18 करोड़ से अधिक

जनता के सामने 10 साल तक फंड की कमी का राग अलापने वाले केजरीवाल के पास कहां से आया यह धन?

-विजया पाठक

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देश में लोकपाल की नियुक्तियों को लेकर वर्ष 2011 में एक आंदोलन छेड़ा। यह आंदोलन इतना प्रभावी रहा है कि अन्ना हजारे का दामन थामने को कई राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और अफसरों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्हीं में से एक थे अरविंद केजरीवाल। वित्त सेवा के अधिकारी पद से सेवानिवृत्ति लेकर केजरीवाल ने एक सोशल कॉज के लिए हजारे का दामन तो थाम लिया लेकिन उन्होंने कुछ ही दिन में इस बात को भांप लिया था कि इस तरह से आंदोलन कार्यकर्ता के रूप में उनके जीवन का उद्धार नहीं हो पायेगा। (शेष पेज 3 पर)

बिजनेसमैन दिलीप सूर्यवंशी ने भाजपा को दिया 29 करोड़ का चंदा

(पेज 1 से जारी)

खास बात यह है कि दिलीप सूर्यवंशी को भाजपा सरकार की छत्र छाया में काफी फलने फूलने का अवसर मिला। सूत्रों के अनुसार दिलीप सूर्यवंशी ने लंबे समय तक चुनाव और इसके अलावा अन्य कार्यों में काफी आर्थिक सहयोग दिया है।

आखिर किसके सहयोग से गिरी कमलनाथ सरकार

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जब वर्ष 2020 में जब भाजपा नेताओं ने कमलनाथ की सरकार गिराने की योजना बनाई उस समय खरीदे गए कांग्रसी नेताओं को दी जाने वाली 200 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई थी। अब यह रकम किसने कैसे दी, इसकी जांच जरूरी है।

सत्ताधारी बीजेपी को चंदा देने के मामले में देश के टॉप 10 में है दिलीप बिल्डकॉन

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में सुर्खियों में रहे दिलीप बिल्डकॉन के मालिक दिलीप सूर्यवंशी राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के मामले में देश के बड़े दानदाताओं में शुमार हो गए हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष देश के राजनीतिक दलों को 2544 करोड़ से ज्यादा चंदा मिला। सबसे ज्यादा 2243 करोड़ भाजपा को मिले, जबकि कांग्रेस को मात्र 281 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले। रिपोर्ट में 20 हजार रुपए से ज्यादा चंदा देने वालों का जिक्र किया गया है। खास बात यह कि मध्यप्रदेश के चर्चित बिल्डर दिलीप बिल्डकॉन के मालिक सूर्यवंशी देश के सबसे बड़े राजनीतिक चंदा देने वालों की सूची में शामिल हैं।

कुल इतना मिला भाजपा को कुल चंदा

इस वर्ष में भाजपा को जो चंदा मिला वह कांग्रेस, आप, एनपीईपी और सीपीआई (एम) को मिले चंदे से 06 गुना ज्यादा है। राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे में 89 फीसदी (करीब 2262 करोड़ रुपए) कॉरपोरेट और व्यावसायिक क्षेत्रों से मिला। इसमें 2064 करोड़ भाजपा को, कांग्रेस को 190 करोड़ रुपए चंदा मिला। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में सभी राष्ट्रीय दलों को 1693 करोड़ का चंदा ज्यादा मिला। पूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को 723.6 करोड़ और कांग्रेस को 156.4 करोड़ रुपए दान दिया। ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को 127.50 करोड़ रुपए चंदा दिया। दिलीप बिल्डकॉन ने भाजपा को 29 करोड़ और क्रोटेक डेवलपर्स ने 27 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया। दिलीप बिल्डकॉन देश के दस बड़े दानदाताओं की सूची में 9वें नंबर पर हैं। उनका नाम प्रदेश में सड़कें, पुल आदि बनाने को लेकर सुर्खियों में रहा है। उंदर घोटाले में भी दिलीप बिल्डकॉन का नाम सामने आ चुका है।

चंदे का 88 फीसदी भाजपा के हिस्से में

वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के छह राष्ट्रीय दलों को मिले कुल चंदे का 88 फीसदी से ज्यादा 2243 करोड़ रुपए भाजपा को मिले, जो 2022-23 की तुलना में 1524 करोड़ रुपए अधिक है। हालांकि कांग्रेस के चंदे में भी भारी उछाल आया है, वहीं बसपा को एक रुपए का भी चंदा नहीं मिला।

सीबीआई ने की थीं छापेमारी

आरोप है कि दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने NHAI के रीजनल ऑफिसर अकील अहमद को 20 लाख रुपये की रिश्वत दी थी। इसी सिलसिले में सीबीआई ने दिलीप बिल्डकॉन के नई दिल्ली, बेंगलुरू, कोचिन, गुड़गांव और भोपाल स्थित दफ्तरों में छापे मारे और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। सीबीआई ने कहा है कि इन जगहों पर की गई कार्रवाई में करीब 4 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों को संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली टीम की कार्रवाई के बारे में लोकल पुलिस और CBI भोपाल के अफसरों को भनक तक नहीं लगी।

दिलीप बिल्डकॉन ने हाल में ही खरीदा है एक चार्टर्ड प्लेन

विलासिता में रहने वाले इनके पुत्र रोहन सूर्यवंशी एवं करण सूर्यवंशी पार्टी के भी शौकीन है, इन्होंने इसके लिए अपने होटल ताज लेकफ्रंट में एक सूईट भी बनवाया है। इसी कड़ी में हाल ही में इन्होंने करोड़ों रुपये का चार्टर्ड प्लेन भी खरीदा है। खैर यह प्लेन खरीदे या रॉकेट पर पिछले 20 सालों में जो साम्राज्य खड़ा हुआ उसकी नींव की जांच बहुत जरूरी है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सेना पर उठाया सवाल

पहलगाम हमले के आतंकियों के समर्थन में उतरे भ्रष्टाचारी कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, केंद्र सरकार बघेल पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगाने पर आपातकालीन कार्यवाही

(पेज 1 से जारी)

जबकि देखा जाए तो यह समय देश में एकजुटता दिखाने और मजबूती दिखाने का समय है। लेकिन भूपेश बघेल ने अपने हल्केपन का उदाहरण पेश करते हुए भारत सरकार और देश की सेना पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखा जाए तो यह पहला अवसर नहीं है जब बघेल ने इस तरह का निंदनीय कदम उठाया हो, इससे पहले भी बघेल देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि केंद्र सरकार बघेल के इस रवैए पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत बड़ी कार्यवाही कर सकती है।

पहले अपनी गिरेबान झांक लें बघेल

देश के दुश्मनों की पैरवी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और दुराचार का बीज बोया है वह कार्य देश के दुश्मनों से कम नहीं है। बघेल ने राज्य की जनता को वर्षों तक धोखे में रखकर जो घिनौना कार्य किया है वह किसी पाप से कम नहीं है। देखा जाए तो बघेल को इस घिनौने कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही कर देश के नेताओं के सामने एक मिसाल पेश करना चाहिए। कुल मिलाकर बघेल देश के दुश्मनों की पैरवी करने के बजाए पहले अपने गिरेबान में झांके उसके बाद ही देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करें।

बघेल के समय हुए सबसे अधिक नक्सली हमले

भूपेश बघेल ने पहलगाम आतंकी हमले की तुलना 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले से की है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से पहले दोनों जगहों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी और पहलगाम हमले में दो समानता है। एक में नाम पूछकर मारा गया और दूसरे में धर्म पूछकर। उल्लेखनीय है कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी की 'परिवर्तन रैली' के दौरान नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोग मारे गए थे। बघेल ने कहा कि पहलगाम हमले ने झीरम घाटी नक्सली हमले की याद दिला दी। पहलगाम हमले और झीरम घाटी हमले में दो समानताएं हैं। झीरम घाटी हमले में नक्सलियों ने लोगों का नाम पूछकर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने पूछा था कि नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल (नंद कुमार पटेल के बेटे) और महेंद्र कर्मा कौन हैं। पहलगाम में आतंकियों ने लोगों के नाम और उनका धर्म भी पूछा। दूसरी समानता यह है कि दोनों घटनाओं के समय सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे।

बघेल ने माना आतंकवाद समाप्त नहीं

भूपेश बघेल के अनुसार नक्सलवाद अभी छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समस्या अब राज्य में है, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं। जाहिर है कि बघेल के कार्यकाल के दौरान राज्य में बड़ी संख्या में नक्सली हमले हुए थे जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में 2 जनवरी 2023 को स्थानीय लोगों ने सामाजिक बैठक आयोजित की थी. यह बैठक पुलिस की निगरानी में हुई थी और बैठक की जानकारी पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके बताई थी। बैठक के दौरान लकड़ी, डंडे से लैस कुछ झुंड अलग हुए और स्कूल परिसर में स्थित विशेष समुदाय के थाना भवन में पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। जिसमें जीजस और मैरी की मूर्ति को खंडित किया। इस दौरान पथराव भी किया गया और पथराव की चपेट में जिले के एसपी सदानंद कुमार के सिर में चोट आई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया।

कमलनाथ, अरूण यादव, सचिन पायलट, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत जैसे कर्मठ नेताओं को सौंपी जाये राज्यों की कमान

(पेज 1 से जारी)

लोकसभा में पार्टी के 99 सांसद हैं और कई राज्यों में सरकार भी है लेकिन यह ग्राफ बढ़ाना होगा। खासकर राज्यों में तो पार्टी को मजबूती प्रदान करनी होगी। क्योंकि जब तक राज्यों में कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक देश में मजबूत नहीं होगी। इसलिए कांग्रेस को राष्ट्र से पहले राज्यों पर फोकस करना होगा। इसके अलावा संगठन को भी मजबूत बनाना होगा। राहुल गाँधी अपनी कांग्रेस पार्टी को धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले ख़ेमे में रखते हैं जो उनके अनुसार 'आरएसएस-बीजेपी जैसी नफ़रत फैलाने वाली ताक़तों' के ख़िलाफ़ खड़ी है।

हिंदी भाषी राज्यों की अनदेखी पड़ रही भारी

कांग्रेस को हिंदी भाषी राज्यों की अनदेखी भी भारी पड़ रही है। उप्र, मप्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्यों में अभी भी कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टियों को कड़ी टक्कर देने की काबिलियत रखती है। वोट प्रतिशत में ज्यादा कम नही है। सिर्फ सीटों के गणित में ही अन्य पार्टियां भारी हैं। यदि पार्टी एक मिशन को लेकर और स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रबंधन कर ले तो अपने खोये जनाधार को वापस ला सकती है। उल्लेखित यह राज्य ऐसे हैं जहां एक दो बार नहीं बल्कि कई बार कांग्रेस सत्ता में रही है। लेकिन आपसी खींचतान और आलाकमान की अनदेखी के कारण यह राज्य कांग्रेस से हाथों से फिसल गये। ऐसा भी नहीं है कि इन राज्यों में कांग्रेस दोबारा जीवित नहीं हो सकती है। बिल्कुल सत्ता में वापसी हो सकती है। केवल राज्यों में ऐसे नेताओं का चयन करना होगा जो पार्टी के प्रति पूरी कर्मठता और निष्पक्षता के साथ खड़े हों।

कांग्रेस को आज कमलनाथ जैसे समर्पित नेताओं की जरूरत

कांग्रेस में कमलनाथ एक बड़ा नाम है। ये केंद्रीय मंत्री के अलावा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी पूरी राजनीति कांग्रेस के लिए समर्पित की। आज पार्टी को ऐसे ही कर्मठ और ईमानदार नेताओं की जरूरत है। यदि आज भी मध्यप्रदेश में कमलनाथ को सर्वेसर्वा बनाया जाता है तो पार्टी में नई उर्जा का संचार होगा। कार्यकर्ताओं में नया जोश आयेगा। इसका एक कारण भी है क्योंकि कमलनाथ के नेतृत्व में ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 18 माह के शासन में कमलनाथ ने प्रदेश में एक अलग ही छाप छोड़ी है। आज भी लोग कमलनाथ के शासन को याद करते हैं और उनके फैसलों की सराहना करते हैं। लेकिन सूत्रों का मानना है कि मप्र में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की पेड वर्कर पार्टी बन गई है। कांग्रेसी बीजेपी के लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो यहां भी सचिन पायलट प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है। सचिन पायलट प्रदेश में काफी लोकप्रिय हैं। प्रदेश में जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी तब सचिन पायलट का काफी योगदान रहा था। उस समय मुख्यमंत्री पद के यही प्रबल दावेदार थे। अब भी यदि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है या इन्हें प्रदेश की कमान सौंपती है तो निश्चित रूप से राज्य में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव ऐसे नाम हैं जो अपने दम पर प्रदेश में पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। पिछली सरकार में भी यह महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ को इनके जैसे नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत है जो कांग्रेस की पुनः सत्ता में वापसी करा सकें।

राज्यों से निकलती है केंद्रीय सत्ता की चाबी

हम देख रहे हैं कि 2014 से केंद्र में मोदी सरकार की सत्ता है। नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। खासकर हिंदी भाषी राज्यों का तो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज देश के लगभग 70 प्रतिशत राज्यों में बीजेपी का शासन है। जिसकी ही बदौलत केंद्र में मोदी की सरकार है। राज्यों में अपनी सरकार बनाने में बीजेपी पूरी मेहनत करती है। विधानसभा के चुनावों को भी काफी महत्वपूर्ण मानती है। बीजेपी आलाकमान की सत्ता और संगठन पर हर समय पैनी नजर रहती है। पार्टी आलाकमान के बगैर प्रदेश में पत्ता भी नहीं हिलता है। मतलब साफ है कि राज्यों पर अंकुश शीर्ष नेतृत्व का रहता है। यही कारण है कि आज बीजेपी लगभग पूरे देश में सत्ता में है। कांग्रेस को भी अगर केंद्र में सत्ता में आना है तो पहले राज्यों पर पूरा फोकस करना होगा। यदि राज्यों में पार्टी कमजोर रहेगी तो केन्द्र में भी कमजोर रहेगी।

कमलनाथ की दूरदर्शिता और मौजूदा सोच

कमलनाथ की दूरदर्शिता आज के युवा नेताओं के लिए एक मिसाल है। मध्यप्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां संसाधन हैं, युवाशक्ति है और कृषि व उद्योग का विशाल आधार है। हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी, जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध हों, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक सीखने का अवसर मिले। यदि हमें स्वर्णिम भारत के साथ-साथ स्वर्णिम मध्यप्रदेश की ओर बढ़ना है तो कमलनाथ जैसे दूरदर्शी नेता की जरूरत है।

बेटी हर्षिता की शादी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उड़ाये 18 करोड़ से अधिक

(पेज 1 से जारी)

यही कारण है कि केजरीवाल ने हजारे के आंदोलन से कई लोगों तो तोड़कर अपने साथ लिया और वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई। जनता के सामने सामाजिक कार्यों, उनकी परेशानियों को दूर करने और समाज में भेदभाव रहित समाज बनाने का सपना लेकर आगे बढ़े केजरीवाल को जनता का काफी समर्थन मिला और वर्ष 2014 में उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। खैर, आज हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाफ शर्ट, फुल पेंट और पैरों में चप्पल पहनकर सिर पर नेहरु टोपी रखकर हाथ में झाड़ू लिये जनता की सेवा करने के लिए निकलने वाले अरविंद केजरीवाल अचानक से अरबपति कैसे हो गये। आखिर समाज सेवा का राग अलापने वाले केजरीवाल के अंदर से अचानक समाज सेवा का वह भाव कहां गायब हो गया जिसको लेकर वे जनता के घर-घर पहुंचे। महज 10 वर्षों के दिल्ली सरकार में रहते हुए केजरीवाल ने आलीशान शीश महल, लग्जरी गाड़ियां, अरबों की संपत्तियां और फिर हाल ही में करोड़ों रुपये खर्च कर बेटी हर्षिता की शादी आखिर यह सब करने के लिए इस समाजसेवी केजरीवाल के पास पैसा कहां से आया। कुल मिलाकर यह देखने, सुनने और समझने के बाद निष्कर्ष मिलता है कि केजरीवाल और अन्य नेताओं में कोई फर्क नहीं है, सभी नेता शुरुआत में तो समाज सेवा का राग अलापते हुए आपसे वोट की मांग करते हैं लेकिन सत्ता में आते ही राजयोग के मद का सुख उन्हें अपने आगोश में ऐसा समेटता है कि उन्हें हर तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देता है। निःस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए बनाई गई आम आदमी पार्टी आज केवल मैं तक सीमित हो गई है।

18 करोड़ से अधिक शादी पर किये खर्च

सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कनाट पैलेस स्थित एक शानदार लग्जरी होटल से अपनी बेटी हर्षिता की शादी की। शादी में दिल्ली के कई प्रमुख हस्तियों सहित आईएएस, आईपीएस अफसर, नेता, मंत्री और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां शामिल हुई। इन सभी मेहमानों के लिए केजरीवाल ने इस शानदार होटल में जो व्यवस्था की है उसके बारे में जानने के बाद तो केजरीवाल से भरोसा ही उठ जायेगा। जानकारी के अनुसार केजरीवाल ने पूरे शादी समारोह में 18 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया। इसमें शादी समारोह में आने वाले मेहमानों को 16 हजार रुपये प्रतिदिन खर्च वाले कमरों में ठहराया गया, उन्हें 8 हजार रुपये की नाश्ते की थाली उपलब्ध करवाई गई। 13 से 14 हजार रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर केजरीवाल द्वारा बेटी का शादी समारोह का यह जलसा किस पैसे से किया गया है जनता का इसका हिसाब चाहती है।

राजनेताओं के बच्चों की शादियों में खर्चा आम बात

पिछले दो महीने में देश के कई प्रमुख राजनेताओं मंत्रियों और विधायकों के बच्चों की शादियां हुई। फिर बात चाहे मध्यप्रदेश की हो या फिर राजस्थान की। प्रदेश में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री संजय पाठक, डॉ। जेपी नड्डा, दिलीप सुर्यवंशी सहित तमाम नेताओं और व्यापारियों के घरों में वैवाहिक समारोह का आयोजन किया गया। इन नेताओं ने भी अपने यहां शादी समारोह में करोड़ों अरबों रुपये खर्च किये। लेकिन केजरीवाल की बेटी की शादी पर किये गये खर्च की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने पार्टी, कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। हमेशा फंड की कमी का राग अलापने वाले केजरीवाल के पास इतना पैसा कहां से आया यह जांच का विषय है।

सबको दरकिनार कर राजा बन गये केजरीवाल

मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो उस समय में इसमें प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, केजरीवाल सहित योगेन्द्र यादव जैसे प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। धीरे-धीरे केजरीवाल ने अपनी तानाशाही शुरू की और एक-एक करके इन लोगों को पार्टी से दूरी बनाना पड़ी और सभी लोग अपने पुराने कार्यों में जुट गये। अकेले बचे केजरीवाल ने कुछ लोगों को जोड़कर पार्टी को फिर से मजबूती देने का प्रयास किया और पार्टी ने दिल्ली में सत्ता प्राप्त की। खास बात यह है कि केजरीवाल ने जिस ढंग, षड़यंत्र के साथ पार्टी पर पूरा कब्जा बनाया उसे देखने के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी से जनता का विश्वास ही उठ गया।

जनता ने दिया करारा जवाब

पिछले दस वर्षों से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ जो खिलवाड़, धोखा किया है उसे देखते हुए दिल्ली की जनता ने हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में केजरीवाल और उनकी पार्टी को करारा जवाब दिया और पार्टी को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि जिस भाजपा की नीतियों को गलत ठहराते हुए केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, उन्हीं नीतियों के बल पर 29 साल बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई।

सम्पादकीय

सिंधु जल संधि स्थगित होने से पाकिस्तान की बढ़ेगी चिंता

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। यह भारत द्वारा अब तक का सबसे कठोर कदम माना जा रहा है। 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इंडस रिवर वॉटर ट्रीटी सस्पेंड किया जाना पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का बंटवारा करती है। इस संधि के तहत पाकिस्तान निचला तटवर्ती राज्य बन गया है और भारत ऊपरी तटवर्ती राज्य। निचला तटवर्ती राज्य होने का मतलब है जहां नदी समाप्त होती है। वहीं ऊपरी तटवर्ती राज्य का मतलब है जहां नदी का उद्गम होता है। इस संधि के अनुसार, भारत को तीन पूर्वी नदियों- रावी, सतलुज और ब्यास पर विशेष अधिकार प्राप्त हुए। यह लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (MAF) या सिंधु नदी प्रणाली के कुल जल का लगभग 20% है। पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब पर नियंत्रण मिला, जो लगभग 135 MAF या कुल जल का 80% प्राप्त करती हैं। संधि के तहत भारत पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग घरेलू, गैर उपभोग्य और कृषि उद्देश्यों के लिए कर सकता है। भारत को रन-ऑफ-द-रिवर (आरओआर) परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न करने का भी अधिकार है, जो डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन है। संधि के अनुच्छेद IX में विवाद समाधान तंत्र शामिल है। यह एक तीन-स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले, विवादों को स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) के माध्यम से उठाया जाता है। दोनों देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। फिर विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ के माध्यम से और अंतिम उपाय के रूप में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के माध्यम से होती है।

सरल शब्दों में एक नदी, उसकी सहायक नदियों के साथ, एक नदी प्रणाली कहलाती है। सिंधु नदी प्रणाली में छह नदियां शामिल हैं- सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंधु और सतलुज पूर्ववर्ती नदियां हैं, जिसका अर्थ है कि वे हिमालय के निर्माण से पहले भी मौजूद थीं और तिब्बत क्षेत्र में उत्पन्न होने के बाद गहरी घाटियां बनाती थीं। अन्य चार नदियां- झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास भारत में उत्पन्न होती हैं। सिंधु बेसिन चार देशों में फैला हुआ है, इनमें चीन, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। भारत में बेसिन लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में फैला हुआ है। बेसिन का कुल जल निकासी क्षेत्र लगभग 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.8% है। पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए भारत ने रावी पर रंजीत सागर बांध, सतलुज पर भाखड़ा बांध और ब्यास पर पोंग और पंडोह बांध बनाए हैं। इन नदियों पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में ब्यास-सतलुज लिंक, माधोपुर-ब्यास लिंक और इंदिरा गांधी नहर परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं की मदद से भारत पूर्वी नदियों के लगभग 95% पानी का उपयोग करता है।

सियासी गहमागहमी

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर खड़ा किया प्रश्नचिन्ह

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर करारा हमला किया है। आतंकी हमले से आहत लक्ष्मण सिंह ने गृह नगर राघौगढ़ में कैंडल मार्च के बाद श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगा डाला कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से तुरंत समर्थन वापस लेना चाहिए और इस बारे में वह कांग्रेस आलाकमान को लैटर तक लिखेंगे। उन्होंने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को नादान करार देते हुए कहा कि पार्टी को मुझे निकालना है तो निकाल दे।

एक बार फिर बिगड़े मंत्री पटेल के बोल

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसकी अब काफी चर्चा हो रही है। खंडवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद पटेल ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में स्टॉप डैम अगर ईमानदारी से बनते तो एक भी नदी-नाला सूखा नहीं मिलता। इस राज्य में इतने स्टॉप डैम बने हैं कि हर 50 मीटर में नदी-नाले में स्टॉप डैम मिल जाना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। खंडवा में पंच-सरपंच उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री पटेल ने ये बयान मंच से दिया। पटेल ने कहा कि इसलिए मैंने कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाए थे। सरपंच, सचिवों को कहा है कि नाली, सीसी सड़क, बाउंड्रीवॉल और स्टॉपडैम का पैसा मांगने मत आना।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

पहलगाम में हुआ दुस्साहसी आतंकी हमला एक भयावह त्रासदी है। मैं यहां के हालात को समझने और मदद करने आया हूं। जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों ने इस भयावह हमले की निंदा की है और पूरी तरह से देश का समर्थन किया है। मैंने घायल हुए एक व्यक्ति से मुलाकात की। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और स्नेह है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

जब जब मानवता पर हमला होगा कांग्रेस पार्टी मानवता की रक्षा में आगे खड़ी रहेगी।

अपने पिता और दादी को आतंकवाद से संघर्ष में शहीद होते देख चुके राहुल गांधी से अधिक कौन व्यक्ति होगा जो आतंकवाद से मिले दर्द को समझता है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

विलक्षण प्रतिभा के धनी अमित शाह कठिन निर्णय लेने के लिये रखते हैं विशिष्ट पहचान

समता पाठक/जगत प्रवाह

अमित शाह भारत के गृहमंत्री और भाजपा के स्टार पोलिटिशियन हैं जिन्होंने 1997 से भाजपा के लिए सारथी की तरह काम करते रहे। अमित शाह की जाति, जीवनी, परिवार इनके बारे में जानकारी और इतिहास के बारे में आपको यहाँ शाह की जीवनी में एक व्यवसायी का बेटा किस तरह अपने पुश्तैनी बिजनेस को छोड़कर एक संगठन से जुड़ते हैं। अपराजेय और स्पष्ट वक्ता शाह के जीवन की कहानी किसी आदर्श नेता से कहीं बेहतर है। शाह का जन्म एक अमीर व्यवसायी के घर 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने स्कूली पढाई 12वी के बाद पढ़ाई के लिए अहमदाबाद चले गये। यहाँ से इन्होने बॉयोकेमिस्ट्री में बीएससी की डिग्री हासिल की। अपने कॉलेज के दिनों में ही अमित शाह ने आरएसएस और एबीवीपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इनके पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत गुजरात के मुख्यमन्त्री नरेंद्र मोदी के मिलन से हुई। एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान दोनों की भेंट हुई। इसके बाद मोदी-शाह के बिच अच्छी दोस्ती हो गई। जिन्हें आज भी दुनिया सलाम करती है।

शाह ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक प्लास्टिक और पीवीसी पाइप का व्यापार भी किया। मगर उनका मन बिजनेस में कम राजनीति की तरफ अधिक झोले मार रहा था। इन्होंने स्थानीय निकाय से लेकर सांसद और विधायक के पदों के लिए 50 से अधिक चुनाव एक प्रत्याशी की भूमिका से लड़े हैं। वर्ष 2017 तक अमित शाह अपराजेय हैं। अपने जीवन के राजनीतिक करियर में इन्होंने एक बार भी हार का मुंह नही देखा है। विलक्षण प्रतिभा के धनी इस महानेता का पॉलिटिकल करियर और उपलब्धियां इस प्रकार हैं। मोदी और शाह पहली बार 1982 में कॉलेज के दिनों में मिले थे, शायद यह राजनीति में आने का न्योता ही था। एक साल तक अपना बिजनेस करने के बाद 18 साल की उम्र में गुजरात की राजनीति में आ गये। इन्होंने वर्ष 1985 में विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। राजनीति के आरम्भिक दिनों में इन्हें अधिक अनुभव ना होने के कारण कोई विशेष पदभार नही दिया गया। पहला अवसर था जब वर्ष 1990 में राजधानी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार और प्रभावशाली नेता लालकृष्ण आडवाणी के लिए चुनाव प्रचार का पूरा काम शाह को दिया गया। सरखेज विधानसभा सीट से शाह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में की इसके दो साल बाद अहमदाबाद कोपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चुने गये। इसके बाद शाह को गुजरात क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष चुने गये। उस समय GCA के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमन्त्री बनने के बाद अमित शाह को गुजरात क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। शाह सरखेज सीट से चार बार MLA चुने जा चुके। 2002 से 2010 तक शाह गुजरात की केबिनेट का मुख्य चेहरा और मोदी के परम मित्र थे। गुजरात दंगों से पहले हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 75 फीसदी सीट जीती थी। उन चुनावों में शाह ने सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल की। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2019 को गांधीनगर से लड़ा और भारी मतों से विजयी भी हुए। शाह चुनाव जीतने के बाद भारत के गृहमंत्री बने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने में उनका बड़ा योगदान था। ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है।

जल संरक्षण: छोटे-छोटे प्रयास से होगी बड़ी बचत

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। यह बात सच हो या न हो, लेकिन इतना तो सच है कि पानी हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य जरूरत है। आज दिल दुखता है। जब हम बड़े-बड़े जल संरक्षण के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन अपने दैनिक जीवन में छोटी-छोटी लापरवाहियों से हजारों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। यह सच है कि पानी अनमोल है और इसकी कमी भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर और आपके परिवार के छोटे-छोटे प्रयास भी मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? आज हम बात करेंगे उन नन्हें कदमों की, जिन्हें उठाकर आप अपने घर को जल संरक्षण का गढ़ बना सकते हैं। सोचिए, अगर हर गृहिणी, हर छात्र, हर कामकाजी व्यक्ति अपनी दैनिक आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाए, तो हम सामूहिक रूप से कितना पानी बचा सकते हैं! यह पहल अब हमारे हाथ में है। अब इंतजार करने का समय नहीं, बल्कि कुछ करने का समय है। आइए देखें, कैसे आपके घर के छोटे-छोटे कार्य एक बड़ी जल क्रांति ला सकते हैं:

नल की चाबी आपके हाथ में

- ब्रश करते वक्त, शेविंग करते वक्त या बर्तन धोते वक्त नल को खुला छोड़ना अब पुरानी बात हुई। जब पानी की जरूरत न हो तो नल को तुरंत बंद करें। याद रखें, एक मिनट में बहता हुआ नल कई लीटर पानी बर्बाद कर देता है।
- लीक होते हुए नल और पाइपों को अनदेखा न करें। एक छोटा सा रिसाव भी साल भर में हजारों लीटर पानी की हानि कर सकता है। तुरंत मिस्त्री को बुलाकर इसे ठीक करवाएं।

प्रकृति का उपहार- वर्षा जल संचयन

- अपनी छत या आँगन में बारिश के पानी को इकट्ठा करने का आसान तरीका खोजें। यह पानी आपके पौधों की प्यास बुझा सकता है, आपकी गाड़ी धो सकता है और घर के अन्य कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- छोटे स्तर पर गड्ढे बनाकर या टैंक स्थापित करके आप इस अनमोल प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग कर सकते हैं।

नहाने का तरीका बदलें, पानी बचाएं

- शावर के नीचे घंटों खड़े रहना अब लग्जरी नहीं, बल्कि पानी की बर्बादी है। बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें, यह न केवल पानी बचाएगा बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी महसूस कराएगा।
- अगर शावर का उपयोग करना ही है तो कम समय के लिए करें और लो-फ्लो शावर हेड का इस्तेमाल करें।

धुलाई में समझदारी

- कपड़े धोने की मशीन को तभी चलाएं जब वह पूरी तरह भरी हो। आधे भरे मशीन को चलाना पानी और बिजली दोनों की बर्बादी है।
- हाथों से कपड़े धोते समय भी नल को लगातार खुला न रखें। बाल्टी में पानी भरकर धोएं।
- बर्तन धोते समय पहले उन्हें सूखे कपड़े से साफ कर लें, फिर कम पानी में धोएं। सिंक में पानी भरकर धोने से भी पानी की बचत होती है।

पौधों को प्यार से पानी दें

- पौधों को पानी देने का सही समय सुबह या शाम है, जब वाष्पीकरण कम होता है।
- ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करें, जो सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाती हैं और बर्बादी को कम करती हैं।

अपनी गाड़ी को भी सिखाएं जल संरक्षण का पाठ

- गाड़ी धोते समय पाइप का इस्तेमाल करने की बजाय बाल्टी में पानी भरकर धोएं।
- कभी-कभी सिर्फ कपड़े से पोंछकर भी सफाई की जा सकती है।

आइए, आज ही संकल्प लें कि हम अपने घरों से जल संरक्षण की इस मुहिम को शुरू करेंगे। अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाएंगे और उन्हें जल योद्धा बनने के लिए प्रेरित करेंगे। "पानी बचाओ, भविष्य बचाओ!" यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है जिसे हमें मिलकर जीना है। आइए, छोटे-छोटे प्रयासों से एक बड़ी क्रांति लाएं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का खजाना सुरक्षित करें।

सिंधु जल संधि पर रोक

पाकिस्तान से पानी का रिश्ता हुआ समाप्त

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पांच बड़े कूटनीतिक प्रहार कर दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना है। यह एक ऐसी कूटनीतिक चाल है, जिससे पाकिस्तान को भीषण जलसंकट का सामना तो करना पड़ेगा ही आर्थिक समृद्धि में भी यह फैसला मठा घोलने का काम करेगा। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करते हुए उन्हें 48 घंटे में पाक लौट जाने का आदेश दिया है। अटारी-वाघा सीमा-द्वार बंद कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान से अपने सैन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। इन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ना होगा। ये सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा समिति (सीसीएस) की बैठक में लिए गए हैं। आतंकवादियों की शरणस्थली बने पाकिस्तान को ये कूटनीतिक सबक समय की जरूरत है।

अमानुशिक दगाबाजी के आदि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के 'गले की नस' है। पाकिस्तान ने आतंकी साजिश रचकर कश्मीर के अवाम की इसी आर्थिक श्वास की नली को अवरुद्ध कर दिया है। अब भारत ने पलटवार करते हुए सिंधु की जलधार को अवरुद्ध करके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है। यदि यह जवाब बहुत पहले दे दिया गया होता तो शायद पाक से निर्यात आतंक के ये हालात पनप ही नहीं पाते? 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि में भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों का पानी बांटने का समझौता हुआ था। इस समझौते पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसके अंतर्गत पाकिस्तान से पूर्वी क्षेत्र की तीन नदियों व्यास, रावी व सतलुज की जल राशि पर नियंत्रण भारत के सुपुर्द किया गया था और पश्चिम की नदियों सिंधु, चिनाब व झेलम पर नियंत्रण की जिम्मेदारी पाक को सौंपी गई थी। इसके तहत भारत के ऊपरी हिस्से में बहने वाली इन छह नदियों का 80.52 यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी पाकिस्तान को हर साल दिया जाता है। जबकि भारत के हिस्से में महज 19.48 प्रतिशत पानी ही शेष रह जाता है। नदियों की ऊपरी धारा (भारत में बहने वाला पानी) के जल-बंटवारे में उदारता की ऐसी अनूठी मिसाल दुनिया के किसी भी अन्य जल-समझौते में देखने में नहीं आई है। इसीलिए अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों से संबंधित समिति ने 2011 में दावा किया था कि यह संधि दुनिया की सफलतम संधियों में से एक है। लेकिन यह संधि केवल इसलिए सफल है, क्योंकि भारत संधियों की शर्तों को निभाने के प्रति अब तक उदार एवं प्रतिबद्ध बना हुआ है। जबकि जम्मू-कश्मीर को हर साल इस संधि के पालन में करीब 60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत की भूमि पर इन नदियों का अकूत जल भंडार होने के बावजूद इस संधि के चलते इस राज्य को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई इन्हीं नदियों के जल से होती है। पाक के बड़े भू-भाग की 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल की जरूरतें इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं। यह संधि लंबे समय तक स्थगित रहती है तो पाकिस्तान में अकाल और सूखे के हालात बन सकते हैं।

दरअसल सिंधु-संधि के तहत उत्तर से दक्षिण को बांटने वाली एक रेखा सुनिश्चित की गई है। इसके तहत सिंधु क्षेत्र में आने वाली तीन नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम पूरी तरह पाकिस्तान को उपहार में दे दी गई हैं। इसके उलट भारतीय संप्रभुता क्षेत्र में आने वाली व्यास, रावी व सतलुज नदियों के बचे हुए हिस्से में ही जल सीमित रह गया है। इस लिहाज से यह संधि दुनिया की ऐसी इकलौती अंतरदेशीय जल संधि है, जिसमें सीमित संप्रभुता का सिद्धांत लागू होता है और संधि की असमान शर्तों के चलते ऊपरी जलधारा वाला देश नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा वाले देश पाकिस्तान के लिए अपने हितों की न केवल अनदेखी करता है, वरन बलिदान कर देता है। इतनी बेजोड़ और पाक हितकारी संधि होने के बावजूद पाक ने भारत की उदार शालीनता का उत्तर पूरे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में आतंकी हमलों के रूप में तो दिया ही, अब इनका विस्तार भारतीय सेना व पुलिस के सुरक्षित ठिकानों तक भी किया हुआ है। अब पर्यटकों की हिंदू धार्मिक पहचान करके जो नरसंहार पहलगाम की बैसरन घाटी में किया है, वह यह जताने के लिए काफी है कि हमला धर्म के आधार पर किया गया है। ये सभी हमले आतंकवाद को बहाना बनाकर छद्म युद्ध के जरिए किए गए, जबकि ये सभी हमले पाक सेना की करतूत हैं। दरअसल छद्म युद्ध में लागत तो कम आती ही है, हमलावर देश पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर इस बहाने रक्षात्मक भी हो जाता है कि इन हमलों में उसका नहीं, आतंकवादियों का हाथ है। बावजूद हैरानी इस बात पर है कि इस संधि को तोड़ने की हिम्मत न तो 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद दिखाई गई और न ही 1971 में? हालांकि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित कर नए राष्ट्र बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने की बड़ी कूट व रणनीतिक सफलता हासिल की थी। कारगिल युद्ध के समय भी हम इस संधि को तोड़ने से चुके हैं। देर से ही सही इस संधि को तोड़ने की पहल देशहित में है।

दरअसल पाकिस्तान की प्रकृति में ही अहसानफरोसी शुमार है। इसीलिए भारत ने जब झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर बनने वाली 'किशन गंगा जल विद्युत परियोजना' की बुनियाद रखी तो पाकिस्तान ने बुनियाद रखते ही नीदरलैंड में स्थित 'अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय' में 2010 में ही आपत्ति दर्ज करा दी थी। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में किशनगंगा नदी पर 300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। हालांकि 20 दिसंबर 2013 को इसका फैसला भी हो गया। दुर्भाग्य कहलें या भारत द्वारा ठीक से अपने पक्ष की पैरवी नहीं करने के कारण यह निर्णय भारत के व्यापक हित साधे रखने में असफल रहा है। न्यायालय ने भारत को परियोजना निर्माण की अनुमति तो दे दी, लेकिन भारत को बाध्य किया गया कि वह 'रन ऑफ दि रिवर' प्रणाली के तहत नदियों का प्रवाह निरंतर जारी रखे। फैसले के मुताबिक किशनगंगा नदी में पूरे साल हर समय 9 क्यूसेक मीटर प्रति सेकंड का न्यूनतम जल प्रवाह जारी रहेगा। हालांकि पाकिस्तान ने अपील में 100 क्यूसेक मीटर प्रति सेकंड पानी के प्राकृतिक प्रवाह की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने नहीं माना। पाकिस्तान ने सिंधु जल-समझौते का उल्लंघन मानते हुए भारत के खिलाफ यह अपील दायर की थी। इसके पहले पाकिस्तान ने बगलिहार जल विद्युत परियोजना पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसे विश्व बैंक ने निरस्त कर दिया था।

दरअसल द्विपक्षीय वार्ता के बाद शिमला समझौते में स्पष्ट उल्लेख है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत के खिलाफ आतंकवाद को फैलाने की इजाजत नहीं देगा। किंतु पाकिस्तान इस समझौते के लागू होने के बाद से ही, इसका खुला उल्लंघन कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के नजरिए से भारत को सिंधु जल-संधि को ठुकरा कर पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। पुलवामा हमले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों का पानी रोकने की बात कही थी। भारत ने अब इस मांग को अंजाम तक पहुंचा दिया है। तय है, इस कूटनीतिक पहल से पाक की कमर टूट जाएगी। नदियों के प्रवाह को बाधित करना इसलिए भी अनुचित नहीं है, क्योंकि यह संधि भारत के अपने राज्य जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए न केवल औद्योगिक व कृषि उत्पादन हेतु पानी के दोहन में बाधा बन रही है, बल्कि पेयजल के लिए नए संसाधन निर्माण में भी बाधा है। इस संधि के चलते यहां की जनता को पानी के उपयोग के मौलिक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा था। हैरानी की बात यह भी है कि यहां सत्तारूढ़ रहने वाली सरकारों और अलगाववादी जमातों ने इस बुनियादी मुद्दे को उछालकर पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कभी नहीं की? इसलिए आतंक का माकूल जवाब देने के लिए भारत सरकार की इस कूटनीतिक पहल का स्वागत होना चाहिए।

बहुचर्चित डेरा सच्चा सौदा जमीन फर्जीवाड़ा मामले में जमानत पर सुनवाई आगे बढ़ी

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह, नर्मदापुरम। नगर के बहुचर्चित डेरा सच्चा सौदा जमीन फर्जीवाड़ा मामले में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा न्यायालय से अनुमति लेकर एफआईआर में चार नए आरोपी बनाए गए हैं। जिसमें शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील गोयल, उनके दोनों बेटे दिव्यांश और एकांश सहित आरपी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी बनाए गए अधिवक्ता सुशील गोयल सहित उनके बेटे फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। फरार आरोपियों द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया हुआ है जिस पर सुनवाई होनी थी जो कि अब तिथि आगे बढ़ गई है। जिस पर अब 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। मामले में अधिवक्ता संजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता संतोष जैन के आवेदन पर जांच उपरांत न्यायालय से अनुमति से आरोपियों के नाम बढ़ाए हैं। कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी थी जिसे हम आपत्ति विरोध करने के लिए उपस्थित भी हुए परंतु अब सुनवाई आगे बढ़ गई है और 30 अप्रैल को आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होगी। हमने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर ओमप्रकाश बरेठा की सच्चाई सामने लाई जा सके, जिससे पूरी स्थिति सामने स्पष्ट होगी। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी से ही ओमप्रकाश बरेठा की पहचान हो सकेगी। इसलिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। प्रकरण में फर्जी व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले नकली मदनलाल का मामला भी सामने आया था। जिसमें भी अधिवक्ता सुशील गोयल शामिल थे।अधिवक्ता संजय मिश्रा ने बताया कि आगामी सुनवाई में न्यायालय में आरोपियों की अग्रिम जमानत पर विरोध दर्ज कराएंगे। एसडीओपी पराग सैनी ने बताया कि प्रकरण में आरोपी फरार हैं, जिनको गिरफ्तार करने का पुलिस प्रयास कर रही है।

राजस्व विभाग के कार्यों से शासन की छवि निखरती है: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग का सीधा संबंध आम जनता से है, मैदानी अमले की लापरवाही शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने और सभी आवेदनों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय का संचालन सप्ताह में न्यूनतम दो दिन अनिवार्य रूप से किया जाए और दो पेशी में ही प्रकरणों का निराकरण हो। अति आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर पेशी की तिथि बढ़ाने से बचा जाए। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का त्वरित और सहज लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने फौती नामांतरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि विधिक वारिसान के पक्ष में फौती नामांतरण समय पर सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तय समय सीमा में नामांतरण न होने पर संबंधित पटवारियों की जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आरबीसी 6-4 के अंतर्गत पीड़ित परिवारों को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही में विलंब न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवारों को लंबे समय तक भटकना न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को इसकी सतत निगरानी करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग कर डायवर्सन प्रक्रिया को सरल और सहज बनाने पर भी बल दिया।

उन्होंने अविवादित नामांतरण और बंटवारे के मामलों में अनावश्यक विलंब करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा करते हुए उन्होंने राजस्व, कृषि, खाद्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभागों की संयुक्त टीम गठित कर भूमि और फसल से संबंधित सटीक जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए। राजस्व सचिव श्री अविनाश चंपावत ने विभागीय कार्यों और गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, पंजीयन का डिजिटलीकरण तथा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का कार्य पूर्णता की ओर है। साथ ही उन्होंने राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के डिजिटलीकरण, किसान पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और जियो-रेफरेंसिंग कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया। श्री चंपावत ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री साय के पूर्व निर्देशों के अनुरूप जिलों में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण नियमित रूप से किया जा रहा है।

राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही जमीन की खरीदी-बिक्री सुनिश्चित की जाए और राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर भू-धारकों को शीघ्र राहत दी जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, डॉ. बसवराजु, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में हर नागरिक और व्यवसायी को सरकारी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिलें। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को शामिल करना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सुधार न केवल जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, बल्कि राज्य में निवेश और विकास को भी नई गति देगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सुधार लागू किया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है, ताकि नागरिकों और व्यवसायियों को समय पर सेवाएं मिलें। इन विभागों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सीईसीबी, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग शामिल हैं। इस कदम से मंजूरी और अनुमति की प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी होगी, जिससे पारदर्शिता, कार्यक्षमता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत, इन 13 सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन अनिवार्य होगा। यदि कोई विभाग समय पर सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यह प्रणाली न केवल सरकारी कामकाज को गति देगी, बल्कि नागरिकों और व्यवसायियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेगी।

शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी में विश्व पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण शिक्षण

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी में ईको क्लब द्वारा पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पृथ्वी के संरक्षण के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण के महत्व को समझाना था। ईको क्लब प्रभारी डॉ. सादिया पटेल ने विद्यार्थियों को विश्व पृथ्वी दिवस के इतिहास और उद्देश्य से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि हर वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और पृथ्वी को बचाने के लिए कदम उठाएं। इस वर्ष की थीम हमारी शक्ति, हमारा ग्रह, पृथ्वी के संरक्षण में हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान की अहमियत को दर्शाती है। कार्यक्रम के दौरान, महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भाग लिया। विद्यार्थियों ने सुंदर और रंग-बिरंगे पोस्टर बनाए, जिनमें पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित संदेश दिए गए थे। साथ ही पृथ्वी के संरक्षण के लिए नारे लिखे गए। नारे लेखन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरक और उत्साहवर्धक नारे प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में छात्रा रितिका गुर्जर ने पृथ्वी के संरक्षण पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और हमें अपनी छोटी-छोटी आदतों को सुधार कर इस दिशा में योगदान देना चाहिए। हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। डॉ. संजय कुमार पटवा ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों के दायित्व पर जोर दिया और बताया कि शिक्षा और जागरूकता से ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जे. के. जैन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वी की सुरक्षा हमारे हाथ में है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी छोटी-छोटी आदतों पर ध्यान दें, जैसे जल और बिजली की बचत करना, अपशिष्ट का सही निपटान करना और वृक्षारोपण करना। उन्होंने यह भी कहा कि खुद से पहल करना आवश्यक है, तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। कार्यक्रम का समापन पृथ्वी के संरक्षण के लिए एक शपथ से हुआ, जिसे डॉ. सादिया पटेल ने विद्यार्थियों और उपस्थित प्राध्यापकों को दिलवाई। शपथ में यह संकल्प लिया गया कि हम पृथ्वी के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएंगे और अपनी दिनचर्या में पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाएंगे। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के रूसा और वल्र्ड बैंक प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह तड़वाल, भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ प्रभारी मीनाक्षी यादव, आईटी प्रकोष्ठ प्रभारी सुरभि चौरे सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे।

आनंद विहार स्कूल के तेजस बाथम ने जीती इन्टर स्कूल ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. भोपाल। 26 अप्रैल 25 को आईईएस पब्लिक स्कूल ने इन्टर स्कूल ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है। इस स्पर्धा में भोपाल के समस्त स्कूल ने भाग लिया, जिसमें से आनंद विहार स्कूल के विद्यार्थी तेजस बाथम ने एक गोल्ड एवं एक सिल्वर समेत 02 मेडल जीतकर अंडर 14 वर्ष आयु केटेगरी में जीत हासिल कर चैंपियनशीप उठाई। समापन सेरेमनी पर आईईएस पब्लिक स्कूल के प्रिन्सिपल एवं मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल स्विमिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश स्विमिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राम खिलरानी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। भोपाल के कुल 50 स्कूलों के 150 बच्चों ने भाग लिया। आनंद विहार स्कूल के तेजस बाथम के अलावा आईईएस पब्लिक स्कूल की तीशा पंथी का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा।

हम 'पर्यावरण' से हैं, 'पर्यावरण' हमसे नहीं

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

आज जब धरती की धड़कनें थमने के कगार पर हैं, तब यह वाक्य हमें गहराई से झकझोर देता है, "हम 'पर्यावरण' से हैं, 'पर्यावरण' हमसे नहीं।" हमारी समृद्धि, हमारी रक्षा, हमारी पहचान, सब कुछ इस देहाती, जंगली और अनंत सृष्टि में निहित है, जो हम खुद ही खोते जा रहे हैं। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी नियति और अस्मिता का उद्घोष है। हम प्रकृति की गोद में पलकर बड़े हुए हैं। हमारे पुरखों ने मिट्टी में हाथ डालकर अनाज उगाया, नदियों में टिका कर जीवन बसर किया, जंगलों की हरी-भरी चादर में ठहर कर खुद को पाया। यही कारण है कि मनुष्य की जड़ें पर्यावरण से इतनी गहरी हैं कि हमारा अस्तित्व उसी पर टिका है। विगत दशकों में हमने अवैज्ञानिक अतिक्रमण, बे रोकटोक वृक्ष वनों की कटाई, नदियों की निर्मम धमनियों में कूड़ा-करकट बहाया। परिणामस्वरूप आज हमारे जंगल जल रहे हैं, मौसम अप्रत्याशित रूप से पागल हो गया है, और जीवन-दायिनी नदियाँ, जो कभी हमारी पीढ़ियों को प्यास से बचाती थीं, अब जहरीले विषाक्त पदार्थों की धारा बहे रही हैं।

देश भर में प्रति वर्ष लाखों हेक्टेयर वन कटते हैं। हिमालय से अरुणाचल तक, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव ने सुखाग्रस्त प्रदेशों में भीषण सूखे और बरसात की अनियमितता ला दी है। कभी जो चक्रवाती तूफान बेहद दुर्लभ हुआ करते थे, आज वे बार-बार दस्तक दे रहे हैं। शहरों की आकाश-सीमा अब जहरीली गैसों से धुंधली हो चुकी है। प्रदूषण के काले बादल गहरे होते जा रहे हैं, और हमारी सांसें घुटने लगती हैं। इन संकेतों ने एक चेतावनी की जन्म दी है कि "पर्यावरण हमसे नहीं"। यह हमारे स्वामित्व का विषय नहीं है। हमारे सरोकार सीमित होते जा रहे हैं। विकास का मतलब केवल इमारतों की ऊँचाइयाँ, सड़कों का विस्तार, उद्योगों की चमक नहीं है। उद्योगों ने जीवन को सुविधाजनक बनाया, लेकिन उसी उद्योग ने वातावरण को विषैला कर दिया। हम भूल गए कि "ऊँचाइयाँ" हासिल करने का अर्थ यह नहीं कि हम धरती को अपने पांवों के नीचे कुचल दें। विकास तब सार्थक है, जब यह प्राकृतिक संतुलन को भंग न करे, बल्कि उसमें सौहार्द और सहजीवन की भावना भर दे। हमारे साथ ही अनेकों जीवों का अस्तित्व उस पर्यावरण से बंधा है जिसे हम अपमानित कर रहे है। तेंदुए से लेकर तितलियों, पत्थर की खदानों से पत्तों पर झूलते भौंरे तक, सभी के जीवन चक्र को हम कठोरता से तोड़ रहे हैं। अवैध शिकार, आवास नष्ट होने से अनेक प्रजातियाँ लुप्तप्राय हो चुकी हैं। कीट, पतंग फसलों की रक्षा के लिए प्रयोग हो रहे कीटनाशकों ने परागण करने वाले कीटों को अक्षम कर दिया, जिससे खाद्य श्रृंखला बाधित हो रही है। नदियों में रसायनों का मिलना, प्लास्टिक कचरा आदि मछलियों और अन्य जलचर प्रजातियाँ दम तोड़ रही हैं। हमारी लापरवाही ने न केवल एक-दो प्रजातियों को समाप्त किया, बल्कि समूचे पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर किया, जिससे अन्न चक्र, जल चक्र और कार्बन चक्र पर संकट मंडरा रहा है।

वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भोजन में मिलावटी पदार्थों ने हमारी सेहत पर भी संकट की घंटियाँ बजा दी हैं। दिन में दर्जनों बार धुंधली आकाशगंगाएँ हमें याद दिलाती हैं कि स्वस्थ जीवन के चारों ओर एक जहरीला घेरे जैसा छा चुका है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। दमा, हैजा, पेचिश आदि रोगों का प्रसार बढ़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य के विनाश ने हमें आंतरिक रूप से भी अशांत कर दिया है। अध्ययन बताते हैं कि हरियाली की कमी से डिप्रेशन और तनाव में बढ़ोतरी होती है।

सरकारों ने कई योजनाएं चलाई है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, पीएम-कुसुम, नेशनल पार्क्स का विस्तार। फिर भी जमीनी हकीकत शर्मनाक है। नीति-निर्माता और उद्योगपति मुनाफे के चक्कर में ईंधन-दहन, खनन, औद्योगिक कचरे का प्रबंधन ढंग से नहीं कर पा रहे। जब तक नीतिगत गंभीरता नहीं आएगी, तब तक "हम पर्यावरण से हैं" का उद्घोष पेट भरने वाला वाक्य ही रहेगा। हमें चाहिए पर्यावरण अपराधों पर त्वरित और व्यापक दंडात्मक प्रावधान, इकाइयों के लिए जीरो-लिक्विड मानक, ईटीपी का अनिवार्य निर्माण, तेल की जगह सौर, पवन, बायोमास को प्राथमिकता। कटे हुए वन पुनःरोपण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी। नीति तभी प्रभावी होगी, जब फाइलों में कैद शाब्दिक प्रतिवेदन नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाले बदलाव हों। जो जिम्मेदारी सरकार पर है, वह नागरिकों के सहयोग के बिना अधूरी है। हमें अपनी दैनिक आदतों में सुधार लाना होगा जैसे साइकिल, पैदल, सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग , पुनः प्रयोगी बैग कांच या स्टील की बोतलों का उपयोग। इन छोटे-छोटे कदमों से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पर्यावरणीय सुधार की लहर दौड़ सकती है। हमारे बच्चों के लिए यह संदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वे नहीं जानेंगे कि कभी आकाश नीला था, नदियाँ निर्मल थीं और जंगल गूंजते थे। यदि हमने अभी सुधार नहीं किया, तो हमारे प्रयास खोखले साबित होंगे। हमें "हम 'पर्यावरण' से है, 'पर्यावरण' हमसे नहीं" का वास्तविक भाव आत्मसात करना होगा।

यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पर्यावरण हमारा स्वामी है। इसका अपमान स्व-अपमान के समान है। हमें इसकी रक्षा करनी है, पोषण करना है, और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, सुंदर और संतुलित विश्व सौंपना है। समय निकल चुका है। अब सिर्फ चिंतन-मनन नहीं, कार्रवाई चाहिए। तभी "हम पर्यावरण से हैं" का अर्थ मिलेगा और "पर्यावरण हमसे नहीं" का दर्पण टूटेगा। हम स्वयं को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी सभ्यता को और अपनी धरती को बचाने के लिए खड़े हों। आज नहीं तो कभी नहीं।

एम्स भोपाल में यौन उत्पीड़न मामलों की जांच में चुनौतियों पर सत्र आयोजित

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में संस्थान में "यौन उत्पीड़न पीड़ितों की जांच में चुनौतियाँ" विषय पर एक सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य यौन उत्पीड़न के मामलों में चिकित्सकीय, मानसिक और कानूनी दृष्टिकोण से प्रशिक्षित करना था, ताकि स्वास्थ्यकर्मी और अन्य संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता और दक्षता के साथ ऐसे मामलों का सही तरीके से निपटान कर सकें। इस सत्र का आयोजन फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग ने किया, जिसमें मेडिसिन, फार्मकोलॉजी, मनोरोग, पैथोलॉजी, बाल रोग, प्रसूति और स्त्री रोग, आपातकालीन चिकित्सा, और नर्सिंग विभागों के 150 से अधिक छात्र, फैकल्टी सदस्य और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भाग लिया। सत्र की शुरुआत डॉ. दीक्षा छाबड़ा (पीजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग) द्वारा यौन उत्पीड़न पीड़ितों की जांच के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रस्तुति से हुई। इसके बाद, डॉ. अवर्णा श्री (पीजी, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग) ने सहमति प्राप्त करने की जटिलताओं पर चर्चा की। प्रस्तुति और स्त्री रोग विभाग की डॉ. श्रेया केंपूवाले और डॉ. कामाक्षी (सीनियर रेजिडेंट्स) ने महिला पीड़ितों के परीक्षण के अनुभव साझा किए। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अपर्णा के. वी. (सीनियर रेजिडेंट) और डॉ. शिवांगी (पीजी, बाल रोग विभाग) ने बाल पीड़ितों की जांच से जुड़ी विशेष चुनौतियों पर बात की। मानसिक स्वास्थ्य पर डॉ. आशीष पखारे (एसोसिएट प्रोफेसर, मनोरोग विभाग) और डॉ. अदिति (पीजी, मनोरोग विभाग) ने पीड़ितों की मानसिक पीड़ा और मनोचिकित्सक की भूमिका पर चर्चा की। एम्स भोपाल के ट्रॉमा और आपातकालीन विभाग की डॉ. देवास्मिता मंडल (पीजी, ट्रॉमा और आपातकालीन चिकित्सा विभाग) ने यौन उत्पीड़न मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को साझा किया। कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर डॉ. जयंती यादव (फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर, प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा, "यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को सिर्फ चिकित्सकीय सहायता नहीं, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और कानूनी सहयोग भी चाहिए। एम्स भोपाल में हमारा उद्देश्य एक ऐसा सहानुभूतिपूर्ण तंत्र बनाना है, जिसमें हर पीड़ित को सम्मान और न्याय मिले। इस प्रकार के सत्र हमारे चिकित्सकों और स्टाफ को संवेदनशीलता और दक्षता के साथ सेवा प्रदान करने के लिए तैयार करते हैं।"

देवरी कृषि उपज मंडी की अव्यवस्थाओं से किसान परेशान

181 पर शिकायत के बाद भी व्यवस्थाओं में नहीं हो रहा सुधार

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी खास। इन दिनों देवरी कृषि उपज मंडी में चारों ओर अव्यवस्थाओं का अंबाला लगा हुआ है। जिसके चलते कृषि उपज मंडी परिसर में आने वाले किसानों और व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कारण किसानों का मंडी से मोहभंग हो रहा है। यह के व्यापारी और किसान समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं। विभिन्न स्तरों पर मंडी की अव्यवस्थाओं की शिकायत की गई फिर भी व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही है। कृषि उपज मंडी परिसर में आवारा पशुओं का आतंक है।सब्जी के किसान और व्यापारी आवारा पशुओं को लेकर परेशान है। क्योंकि जैसे ही माल खुले में रखा जाता है, गाय-बैल जैसे आवारा पशु इन पर टूट पड़ते हैं। जिसके कारण किसान और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मंडी परिषद की नालियों में गंदगी का आलम है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी शुल्क के नाम पर मंडी प्रशासन शुल्क की वसूली तो पूरी करता है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं देता। ग्राम घोसिपट्टी निवासी किसान उमाशंकर लोधी ने मंडी परिषद में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में मुख्यमंत्री शिकायत निवारण 181 में भी शिकायत दर्ज की है। फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही है।181 पर शिकायत दर्ज करते हुए किसान ने बताया कि मंडी परिसर में साफ सफाई नहीं हो रही है और मंडी परिषद में बने शौचालय काफी समय से बंद पड़े हुए है। जिस के कारण किसानों को प्रसाधन के लिए परेशान होना पड़ है। और ना पीने के पानी की व्यवस्था है। आवारा जानवर मंडी परिषद में खुले घूमते रहते हैं। जिसके चलते मंडी परिषद में अवस्थाएं बनी हुई है और देवरी कृषि उपज मंडी में आने वाले किसान और व्यापारी दोनों परेशान है । इसके बावजूद भी मंडी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेपन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)